शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 4, pp (99-103), Month: Dec. 2018

ग्रामीण युवाओ में रोजगार की संभावनाए

डा0 सीमा रानी

असि0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय

जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर, उ0प0,भारत ।

Email: seema.kota1977@gmail.com

सारांश

भारतीय किसान की स्थिति पर नजर डाले तो हालात अच्छे नहीं दिखते है और इसका मुख्य कारण है कि अभी तक हमारी आर्थिक नीतियाँ किसान को केन्द्र में रखने के बजाय कृषि की पैदावार बढ़ाने पर ज्यादा जोर देती रही है। जिसके कारण ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में लाभ नजर नहीं आने के कारण वे आज ग्रामीण कृषि कार्य को अपनाने के स्थान पर नगरों की ओर पलायन करने लगे है। आज यह एक बहुत बड़ी सोच का विषय है। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में ही नयी विकसित तकनीकी के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जिसमें उनका पलायन रोका जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ही उन्हें रोजगार को अवसर प्रदान करने होगें।

मुख्य शब्द *–ग्रामीण युवा, पलायन, कौशल विकास प्रशिक्षण, आर्थिक नीतियाँ।*

प्रस्तावना

हम सभी बचपन से यह वाक्य पढ़ते आए है–''भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।'' लेकिन क्या हमने कभी इस वाक्य के भीतर जो निहित भाव है उस पर बात की है ? वास्तव में यह एक बड़ा सवाल है कि जिस आत्मा की बात हम करते आए है उसे सँवारा कैसे जायेगा? इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि देश की करीब 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अभी भी गाँवों में ही निवास करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिन्ब है। भारत की तस्वीर बिना गाँवों के नहीं बनती है। हमारी आर्थिक प्रगति की दर 8 प्रतिशत के आस–पास रही है, पर इसका पूरा लाभ गाँवों को नहीं मिला है। महानगरों व शहरों में रहने वाली ज्यादातर आबादी को ग्रामीण भारत समस्याए पता ही नहीं होती है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, जमीन के झगड़े, कम उत्पादन व उत्पादकता, सिंचाई की कमी, शिक्षाा का अभाव, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अभाव होने से ग्रामीण युवाओं में चिंता आदि जैसी अनेक समस्याए परेशानी का सबब बनी हुई है।

किसानों की मूलभूत जरूरतों को समझने व उनके लिए जो योजनाएँ बनती है। उन्हें व्यवहारिक बनाने के लिए किसानों से बात करनी होगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में लाभ नजर न आने कारण ग्रामीण युवा कृषि छोड़कर नगरों की ओर पलायन करने लगा है। वर्तमान में यह एक खतरे का संकेत है क्योंकि किसान समाज का अन्नदाता है। कृशि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011 में हुए सामाजिक आर्थिक और जाति सर्वेक्षण अर्थात एस0ई0सी0सी0 के अनुसार देश के कुल 24.39 करोड़ परिवारों में 19.9 करोड़ परिवार गाँवों में

रहते है और अधिकतर कृषि पर निर्भर है। लेकिन जब हम भारतीय किसान की स्थिति पर नजर डाले तो हालात बहुत अच्छे नहीं दिखते और इसका मुख्य कारण है कि अभी तक हमारी आर्थिक नीतियाँ किसान को केन्द्र में रखने के बजाए कृषि की पैदावार बढ़ाने पर ज्यादा जोर देती रही हैं। जिसके कारण ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में लाभ नजर नहीं आने के कारण वे आज ग्रामीण कृषि कार्य को अपनाने के स्थान पर नगरों की ओर पलायन करने लगे है। आज यह एक बहुत बड़ा सोच का विषय है। अतः आज ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में ही नयी–नयी विकसित तकनीकी के उपयोग के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे उनके पलायन को रोका जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ही उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे।

सर हेनरी मेनियों मैकॉफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय एक ''लघु गणतंत्र'' के समान है। जिसमें समुदाय के लोगों का जीवन के एक दूसरे पर निर्भर रहा है। वास्तव में ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र के रूप में गणतंत्र के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता रहा। जैसे आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था, प्रशासन और न्याय। गाँव उत्पादन, उद्यमिता और प्रशासन के मामले में आत्म निर्भर थे। गाँव की आबादी गाँवों में ही रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम थी। समयान्तराल में गाँवों की हैसियत कमजोर पड़ने लगी लेकिन राज्य के लिये आर्थिक स्त्रोत वे पहले की तरह ही रहे। फलस्वरूप ग्रामीण युवा उद्यमिता के अभाव में, अपने भविष्य की तलाश करने शहरों की ओर चल पड़े और पलायन की यह गति निरन्तर बढ़ रही है लेकिन इस पलायन के कारण कुछ प्रश्न हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होते है जैसे कि क्या ग्रामीण युवा व शहरी युवा में उद्यमिता की संभावनाए समान है, क्या आज की सरकारे नगरों की तरह ग्रामीण अँचल में भी उद्यम स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके कि ग्रामीण युवा वहाँ अपने लिए संभावनाए तलाश सकें। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चलता है कि देश के 640 जिलों में रहने वाली शहरी और ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 24.39 करोड़ है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 17.91 करोड़ परिवार रहते है अर्थात लगभग 73 प्रतिशत परिवार ग्रामीण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5.37 करोड़ यानि 29.97 प्रतिशत ग्रामीण भूमिहीन, 51.14 प्रतिशत दैनिक मजदूरी, 30.10 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है। सामान्य स्थिति में भी कृषि में वर्ष भर रोजगार निर्मित नहीं होती इसीलिए ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी/अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी अन्य अतिरिक्त आय की प्राप्ति न होने के कारण, ग्रामीण युवा नगरों की ओर उद्यम की तलाश में पलायन करने लगता है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में कार्य के लिए कुशलता व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः उनकी अकुशलता व प्रशिक्षित न होने के कारण उन्हें नगरों में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में ग्रामीण युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व कौशल निर्माण के लिए अवसर की आवश्यकता है।

आज आवश्यकता इस बात है कि ग्रामीण युवाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से इसके लिये तैयार करें विकसित करें जिससे वह स्वयं रोजगार तलाश न करे बल्कि स्वयं रोजगार पैदा करे। लेकिन क्या ग्रामीण युवाओं में ऐसी संभावनाए मौजूद है। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने हेतु

सरकार द्वारा अनेक ग्रामीण युवाओं के विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

मनरेगाः– सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने और ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर ठाने के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की षुरूआत की गयी थी ताकि भूख, कुपोषण स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके और ग्रामीण जनता रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन ना करें। गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी और व समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेगे। साथ ही शहरों में भीड़–भीड़ से उत्पन्न आवास, बिजली, पानी और आधारभूत सुविधाओं से निजात पा सकेंगे।

मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। इसने ग्रामीण युवाओं को बहुत राहत दी है और यह स्वतः रोजगार का जरिया बन गया है। यह योजना भारत में व्यापक अर्थो में हो रहे बड़े बदलाव में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मनरेगा के अन्तर्गत देश भर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य संसाधन का निर्माण है। उदाहरण के तौर पर देश भर में अनेक कार्य सम्पन्न हुए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में लोगों के खेत के बीचों बीच मनरेगा योजना के अन्तर्गत नाली खोदने से अब खेत पानी में नहीं डूबते और वहाँ सब्जियों की खेती होती है। राजस्थान में बूँदी में नहरे तो है लेकिन उनकी कभी सफाई न होने के कारण पानी का बहाव रूक जाता है वहाँ के गाँवों के बीच इसी पानी को लेकर अक्सर लड़ाई हुई और मामला जिला प्रशासन तक पहुँचा। मनरेगा के अन्तर्गत नहरों की सफाई की गई जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। जहाँ मृतकों का अंतिम संस्कार मुश्किल था, अब वहाँ बीमार व्यक्ति को साईकिल या मोटरसाईकिल पर बैठाकर अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। सार्वजनिक रास्ता बन जाने से दलित समुदाय को भी राहत मिली है क्योंकि सड़क का अधिकार भी झगड़े का मुद्दा बनता था। सुंदरवन में मिट्टी कार्य से लोगों की जाने बचाने का कार्य हुआ है। मनरेगा के जरिये वृक्षारोपण कार्य भी हुए, सड़कों के किनारे, जंगल और पंचायत की जमीन पर, सरकारी परिसरों में और निजी जमीन पर फलदार परिसरों में और निजी जमीन पर फलदार पेड़ लगाये गये। अतः मनरेगा ग्रामीण समाज में होने वाले विकास व बदलाव में एक महत्वपूर्ण औजार साबित हो रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनः–

ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार ने गरीबी कम करने और ग्रामीण युवाओं की आर्थिक स्थिति ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एम०एम०) में एस०जी०एम०वाइ का पुर्नगठन किया। एन०आर०एल०एम० के कार्यन्वयन के लिए फ्रेम वर्क 9 दिसम्बर, 2010 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और मिशन औपचारिक रूप से 3 जून, 2011 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बनाना और पारिवारिक आय को

बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है एन आर एल एम ने स्वयं सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिले, 6000 प्रखण्डों में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों के 7 करोड़ गरीब परिवारों बीपीएल दायरे में लाने का आर 8 से 10 साथ की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प लिया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी०एम०ई०जी० पी०) दो योजनाओं को मिलकर तैयार दिया गया है। वर्ष 2008 से पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) अलग अलग योजनाए थी, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय की सिफारिश पर 14 अगस्त, 2008 को पी०एम०ई०जी०पी० के तहत इसका एकीकरण कर दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की ओर से खादी और ग्रामाधोग आयोग (के०वी० आई०सी०) को एकमात्र नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया। राज्य के खादी ग्रामोधोग बोर्ड व जिला उद्योग केन्द्र भी सहयोगी बनाए गए।

इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त कई तरह के प्रशिक्षण अभी ग्रामीण युवाओं को दिये जा रहे है। जिससे वे जीविकापार्जन कर सके। जैसे–मधुमक्खी पालन, डेयरी विकास योजना, पोल्ट्री विकास, एमू पालन व बकरी पालन इत्यादि।

हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारों की तरह से बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे है जो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं सम्वादों के जरिये उधमिता के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करते है। मुख्य रूप से स्वरोज के लिये प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम आदि।

कौशल विकास एवं उधमिता का मुख्य उद्देश्य उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना और उधमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो देश के सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन न रोजगार का सृजन कर सके। यह नीति अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष ध्यान देने का अभाव प्रशिक्षण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव प्रशिक्षण के लिये अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव आदि सहित कौशल सम्बन्धी प्रमुख बाधाओं को भी दूर करता है। रही बात ग्रामीण युवा की तो पहले गांव में के उधमिता की बुनियाद रखनी होगी। तत्पश्चात् युवाओं को कौशल युक्त बनाकर उस दिशा में मोड़ने की जरूरत होगी। लेकिन अभी इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के समय लगेगा। लेकिन ऐसा करना समय की आवश्यकता है और यही एक श्रेष्ठ विकल्प है, ग्रामीण युवाओं को पलायन से रोकने का ।

सन्दर्भ

1. सिरोही, नरेश, 2018 : *''किसानों की आय दो गुनी करने की दिशा में प्रयास''*, कुरूक्षेत्र, वर्ष 64, अंक–4 फरवरी, 2018, पृ0सं0 **5–10**
2. सिंह, डा0 नरेन्द्रपाल, 2018 : *''सतत ग्रामीण विकास का माध्यम मनरेगा''*–

कुरूक्षेत्र वर्ष 64 अंक–11, सितम्बर 2018, पृ0 **46–48**

3. सिंह, सुधांशु, 2015 : *''जीविकोपार्जन के मिशन पर जुटी सरकार''* कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 12, अक्टूवर, 2015 पृ0सं0 **13–17**
4. सिंह, डा0 रहीश, 2016 : *''ग्रामीणों युवाओं में उद्यमिता की संभावनाएं''* हिन्दी विवेक, नवम्बर, 2016
5. शैलेन्द्र, डा0 एच0एस0, 2018, *राष्ट्रीय आजीविका मिशन*, कुरूक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 11, सितम्बर, 2018 पृ0सं0 **12 से 17**
6. गांव कनेक्शन 2016 : *''ग्रामीण युवाओं को चाहिए बुनियादी शिक्षा''*, जुलाई 2016, www.google.com